

# जनसांख्यिकीय बदलावों को संभालने की कोशिश



केंद्र सरकार ने भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश नावोलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ और "अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन" राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना और संसाधनों के वितरण पर प्रभाव डाल सकते हैं।

## प्रमुख मुद्दे

### 1. जनसांख्यिकीय परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा

#### सरकार का दृष्टिकोण

- अवैध प्रवासन से स्थानीय जनसंख्या की संरचना प्रभावित हो सकती है।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ सकती हैं।
- संसाधनों और कल्याणकारी योजनाओं पर दबाव बढ़ सकता है।

#### उदाहरण

- असम में NRC और नागरिकता संबंधी विवाद।
- सीमा क्षेत्रों में अवैध आव्रजन को लेकर चिंताएँ।

## 2. दस्तावेज-आधारित पहचान की समस्या

यदि नागरिकता और पहचान को केवल दस्तावेजों के आधार पर तय किया जाएगा, तो -

- गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं।
- बड़ी संख्या में लोग "राज्यविहीन" (Stateless) बन सकते हैं।
- मानवीय संकट उत्पन्न हो सकता है।

## 3. सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग का खतरा

किसी विशेष समुदाय, विशेषकर मुसलमानों को जनसांख्यिकीय बहस का केंद्र बनाना सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है।

इससे संविधान के समानता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर प्रभाव पड़ सकता है।

### संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 15 - भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

### भारत की वास्तविक जनसांख्यिकीय चुनौतियाँ

#### (क) घटती प्रजनन दर

भारत का कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 1.9 के आसपास पहुँच चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।

#### (ख) वृद्ध होती आबादी

- 2050 तक भारत में 60+ आयु वर्ग की आबादी लगभग 20% तक पहुँच सकती है।
- इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव बढ़ेगा।

### (ग) जनसांख्यिकीय लाभांश का क्षरण

भारत के पास अभी भी युवा आबादी का लाभ है, लेकिन -

- कौशल की कमी
- बेरोजगारी
- शिक्षा की गुणवत्ता

इसे कमजोर कर सकते हैं।

### 2. प्रवासन (Migration) का महत्व

भारत का इतिहास विभाजन, शरणार्थी आंदोलनों और श्रम प्रवासन से जुड़ा रहा है।

#### सकारात्मक प्रभाव

- श्रम उपलब्धता
- आर्थिक विकास
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान

#### नकारात्मक प्रभाव

- शहरी दबाव
- बुनियादी सेवाओं पर भार

#### आलोचनात्मक विश्लेषण

#### सरकार का पक्ष

- ✓ राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा आवश्यक है।
- ✓ अवैध घुसपैठ को नियंत्रित करना हर संप्रभु राष्ट्र का अधिकार है।
- ✓ संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए जनसंख्या आँकड़ों की सटीकता जरूरी है।

### दूसरा पक्ष

- ✓ जनसांख्यिकीय मुद्दों को केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।
- ✓ मानवीय अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा आवश्यक है।
- ✓ वृद्धावस्था, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि दीर्घकालिक चुनौतियाँ अधिक गंभीर हैं।

केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देश इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ रहे हैं।

'द हिन्दू' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। (16/06/26)

